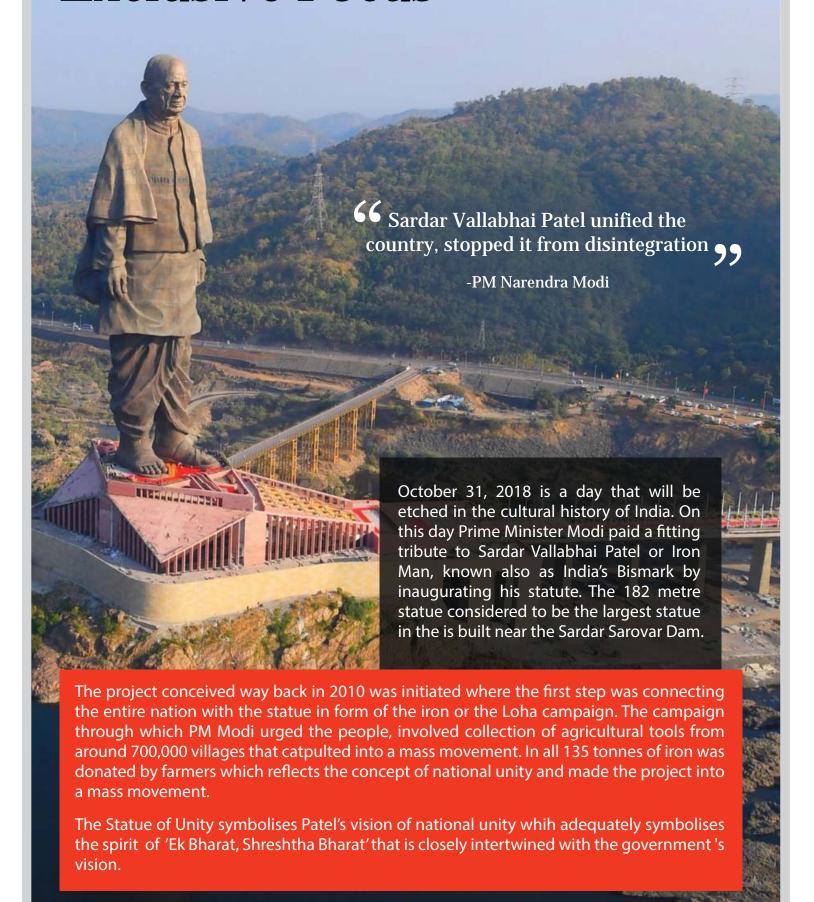
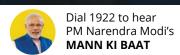


# Exclusive Focus

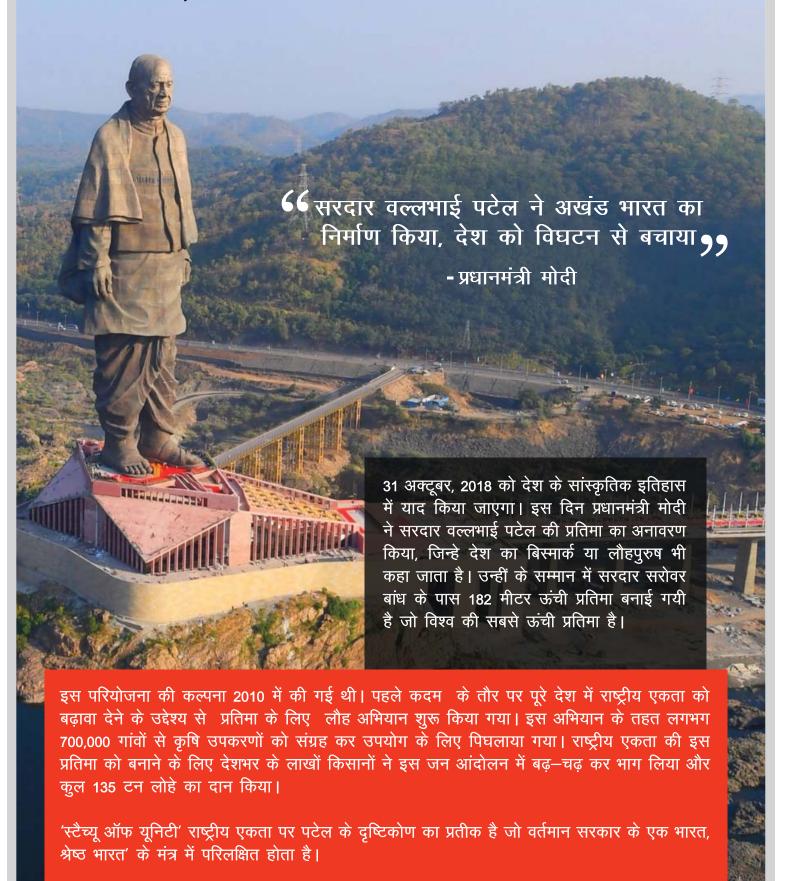


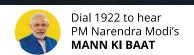








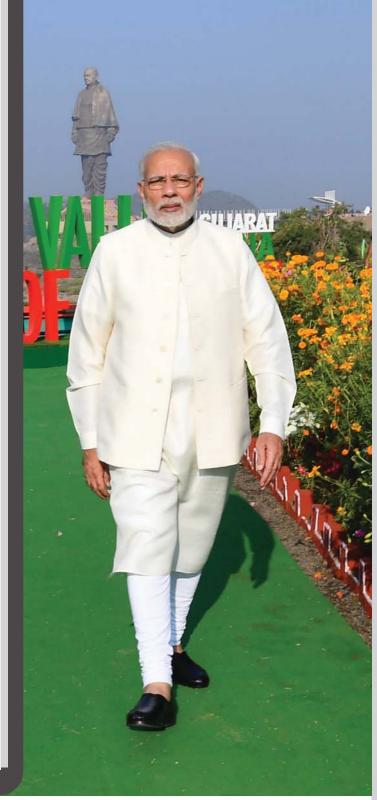






- We are all delighted to be here, on the banks of the Narmada. Today we mark Ekta Diwas. Several people across India are taking part in the Run for Unity
- Today is a day that will be remembered in the history of India. No Indian will ever forget this day
- From the same taste of Sardar Sahib, he merged his states, recognising the power of integration. Given only judging, India became one
- In order to build the Statue of Unity, lakhs of farmers from all over India came together, gave their tools, portions of the soil and thus, a mass movement developed
- From Kutch to Kohima, from Kargil to Kanyakumari today if we are able to go to unabated, it is only possible with their determination, due to the Sardars honour
- Statue of Unity is also symbolic of our engineering and technology affordability. Every day, the artisans have worked on mission mode in around three and a half years.
- These monuments are a symbol of the millions of Indians respecting our strength, and the countrys economy is going to be an important place for job creation. This allows thousands of tribal sister-brothers to get direct employment every year
- Today the entire world is looking at the banks of river Narmada. People from across the country and world are connected to this. We keep the dream of #EkBharatShreshthaBharat alive.

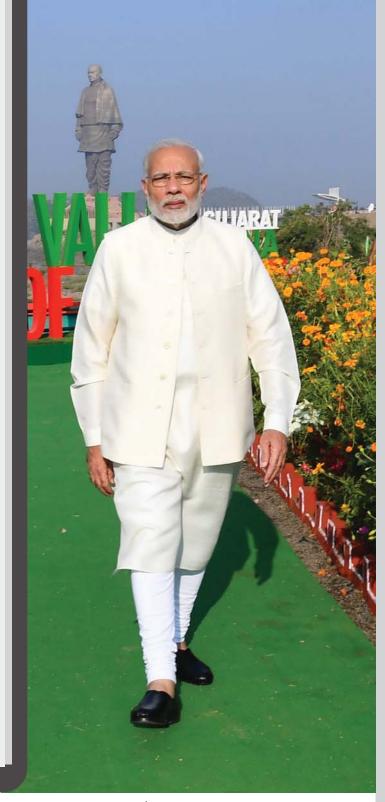


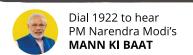




- मां नर्मदा की इस पावन पिवत्र धारा के किनारे पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है। इस अवसर पर देश के कोने—कोने में भारत की एकता और अखंडता के लिए हमारे नौजवान रन फॉर यूनिटी में हिस्सा ले रहे हैं।
- किसी भी देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब वो पूर्णता का एहसास कराते हैं। आज यह वो पल होता है जो किसी राष्ट्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है और उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होता है।
- सरदार साहब के संवाद से एकीकरण की शक्ति को समझते हुए राजा-रजवाड़ों ने अपने राज्यों का विलय कर दिया। देखते ही देखते, भारत एक हो गया।
- राष्ट्रीय एकता की प्रतिमा बनाने के लिए देशभर के लाखों गांवों करोड़ों किसान परिवारों ने खुद आगे बढ़कर इस प्रतिमा के निर्माण को एक जन आंदोलन बना दिया था।
- कच्छ से कोहिमा तक, करिंगल से कन्याकुमारी तक आज अगर बेरोकटोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है।
- महिलाओं को भारत की राजनीति में सक्रिय योगदान का अधिकार देने के पीछे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा रोल रहा है।
- स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य का भी प्रतीक है। बीते करीब साढ़े तीन वर्षों में हर रोज औसतन ढ़ाई हजार कामगारों ने शिल्पकारों ने मिशन मोड पर काम किया है।
- ये स्मारक हमारी ताकत का सम्मान करने वाले लाखों भारतीयों का प्रतीक हैं, और देश की अर्थव्यवस्था नौकरी निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण जगह होगी।

#### प्रतिमा के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के मुख्य अंश









The day marked as the 'Rashtriya Ekta Diwas' also witnessed an overwhelming number of participation in the form of 'Run for Unity' which have been organised across the nation to mark the 143rd birth anniversary of the Sardar Patel.

Remarking that it was Sardar Patel due to whose effort the unification of India was made possible, the PM remarked that the 'New India' built by the 130 crore Indians today is strong, prosperous and inclusive which shows the government's commitment towards 'Last mile delivery of services'.



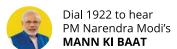


# # RunForUnity

सरदार साहब की 143 वीं जयंती को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया गया और इस दिन आयोजित 'रन फॉर यूनिटी' में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया।

सरदार साहेब के देश के एकीकरण के प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 130 करोड़ देशवासी न्यू इंडिया के निर्माण की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। एक 'नया' मजबूत, समृद्ध और समावेशी भारत के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश का हमारा ध्येय मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है।

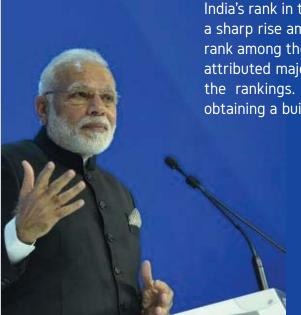






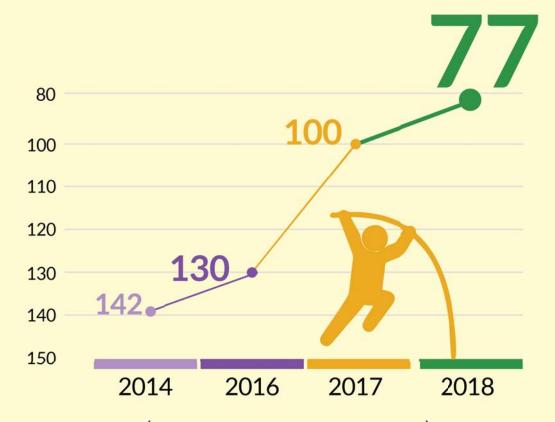
# Top Stories

#### Ease of Doing Business: India takes a giant leap

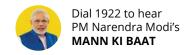


India's rank in the World Bank's Ease of Doing Business 2019 survey projected a sharp rise among the 190 countries surveyed making it the only country to rank among the top 10 improvers for the second consecutive year. The report attributed major policy reforms that contributed towards the positive rise in the rankings. The reforms in India include streamlining the process of obtaining a building permit and improved building quality controls.

Progressive policy measures including introduction of Goods and Service Tax, easy access to electricity, amendment of the insolvency and bankruptcy code and initiatives under the National Trade Facilitation Action Plan (2017-2020) has led to improving its rankings in a number of indicators. The most dramatic improvements were registered in indicators related to construction permit and trading across borders.



(World Bank Ease of Doing Business Rankings)





## प्रमुख समाचार

#### ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेसः भारत की रैंकिंग में ऐतिहासिक बढ़त



वर्ल्ड बैंक की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 सर्वे में भारत की रैंकिंग में ऐतिहासिक बढ़त हुई है। सर्वेक्षण के मुताबिक 190 देशों में लगातार दूसरे वर्ष तेज बढ़त बनाने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत भी शामिल है। विश्व बैंक की ओर से जारी व्यापार सुगमता रैंकिंग में भारत की शानदार बढ़त का कारण देश में कारोबारी माहौल सुधारने के प्रयासों व नीतिगत सुधारों को माना जाता है। सुधारों में आसान प्रक्रिया का निर्माण और बेहतर गुणवत्ता नियंत्रण शामिल है।

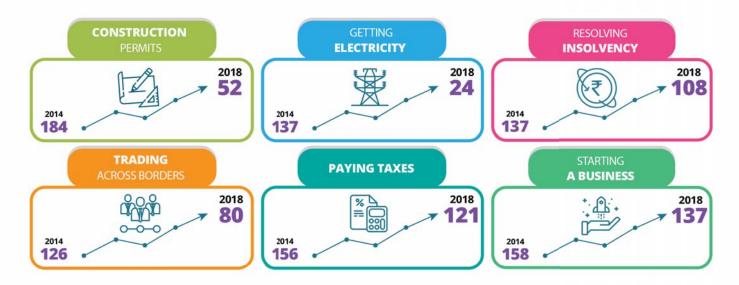
माल और सेवा कर, बिजली की उपलब्धता, दिवाला और दिवालियापन कोड में संशोधन और राष्ट्रीय व्यापार सुविधा योजना (2017—2020) के तहत कई प्रगतिशील उपायों समेत कई अन्य उपायों व संकेतकों से इसकी रैंकिंग में सुधार आया है। विनिर्माण परिमट और सीमा पार व्यापार से संबंधित संकेतकों में सबसे जबर्दस्त सुधार देखे गए।







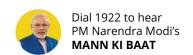
#### Factors on which India's rank improved



# Towards realising 'Shaktiman Bharat': INS Arihant becomes fully operational



India's first indigenous nuclear ballistic missile submarine INS Arihant has become fully operational which completes the country's nuclear triad. The submarine returned from its first deterrence patrol which is a big step towards strengthening national security. It's development and operationalisation not merely attests to the technological prowess but also reflects India's commitment towards it's nuclear doctrine which outlines 'Credible Minimum Deterrence' and 'No First Use' as the posture.





#### भारत की रैंकिंग में सुधार लाने वाले कारक



## 'शक्तिमान भारत' की दिशा में पहलः आईएनएस अरिहंत पूरी तरह से परिचालित

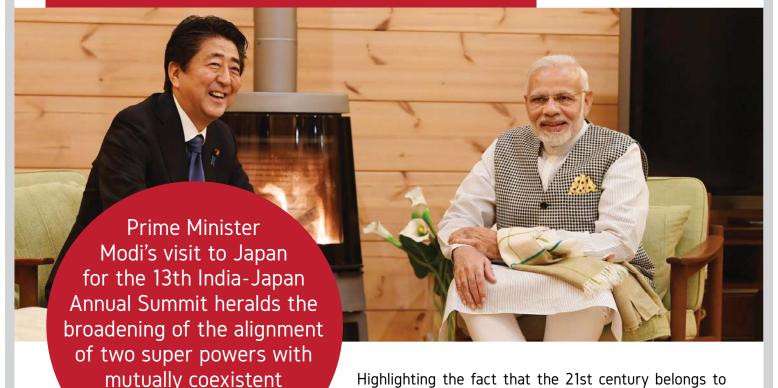


भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत पूरी तरह से परिचालित हो गई है। इसके साथ ही भारत के नाभिकीय त्रिकोण की पूर्ण स्थापना हुई। आइएनएस अरिहन्त हाल ही में अपने पहले डेटरेंस गश्त से लौटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह विकास और परिचालन न केवल तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन करता है बिल्क 'प्रामाणिक न्यूनतम निवारण' और 'प्रथम इस्तेमाल नहीं करने' के सिद्धांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखलाता है।





# Furthering a special and strategic partnership: India and Japan ties



Highlighting the fact that the 21st century belongs to Asia, the PM suggested that the cooperation of both India and Japan is essential to further the Asian power and influence in this century.

#### Some of the key takeaways from his visit include

- Japan and India have inked six pacts on areas including digital partnership, cyberspace, health and protection, space and maritime security.
- Japan will invest \$2.5 million that will provide employment opportunities to over 30 thousand people in India
- Both nations signed currency swap agreements worth \$75 billion which will aid in bringing greater stability to foreign exchange and capital market
- Lauding several initiatives of India including Financial inclusion, arrangements to promote digital transaction, Make in India the government is striving towards Indian Solution :Global Applications

The PM summed up his visit stating that Japan has been a consistent partner of India's development trajectory from bullet trains to smart cities with a major part of Indian youth benefitting from japan's skilling ecosystem.



interests in the

global realm.



## विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को बढ़ावाः भारत—जापान संबंध

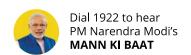


21वीं सदी एशिया की सदी है। इस तथ्य का उल्लेख करते हुए कि प्रधानमंत्री ने 21 वीं शताब्दी के लिए भारत और जापान के बीच सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया है।

#### उनकी यात्रा की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि इस प्रकार है:

- जापान और भारत ने डिजिटल साझेदारी, साइबर स्पेस, स्वास्थ्य और संरक्षण, अंतरिक्ष और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्रों में छह समझौते किए हैं।
- जापान 2.5 मिलियन डॉलर का निवेश करेगा जिससे भारत में 30 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
- दोनों देशों ने 75 बिलियन डॉलर के करेंसी स्वैप समझौतों पर हस्ताक्षर किए जो विदेशी मुद्रा और पूंजी बाजार में स्थिरता को बढ़ावा देंगे।
- वित्तीय समावेश समेत डिजिटल लेन—देन को बढ़ावा जैसे भारत की कई पहलों की सराहना की गई। मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत सरकार ग्लोबल एप्लीकेशन हेतु स्वदेशी समाधान का प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री ने अपनी यात्रा के समापन पर कहा कि जापान बुलेट ट्रेनों से लेकर स्मार्ट शहरों तक की परियोजना के जरिए भारत के विकास का सतत भागीदार रहा है। जापान के स्किलिंग पारिस्थितिक तंत्र से बड़ी तादाद में भारतीय युवा लाभान्वित हो रहे हैं।



के संवर्द्धन और सहयोग को

मजब्ती प्रदान की है।



# Big Boost to the MSME sector, advancing India's Ease of Doing Business

In a crucial move to augment the business climate in the country, the Prime Minister doled out policies that are historic for the MSME sector. While launching the MSME Support and Outreach program, the PM has announced 12 major decisions that would enhance credit access to MSME businesses and lead to an overall development of the economy.



Below given is the graphical depiction of the 12 major decisions and its impact

**(** 

Loan in 59 minutes.



Interest benefits for GST registered MSMEs.



CPSEs and Corporates more than Rs. 500 crore to join Trade Receivables e-Discounting System or the TReDS Platform.



Tech support to MSMEs via 20 hubs and 100 Spokes.



Mandatory 25% procurement from MSMEs by CPSEs.



Now, returns due to 8 Labour Laws and 10 rules to be filed only once instead of the earlier twice.



Pharma Clusters where 70% cost borne by Centre.



All CPSEs to join Government e-Marketplace (GeM).



Of the 25% mandatory procurement, 3% to be done only from women-led MSMEs.



Ending Inspector Raj and ensuring transparency.



Ordinance for simplifying levy of penalties for minor offences.



Easier process for Environmental Clearances and 'Consent to Establish.'

#### The historic decisions ensure:



Easier credit



Wider markets



Better technology



Ease of Doing Business



Safeguarding interests of employees









### कारोबार में सुगमता के प्रयास से एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन

देश में कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई फैसलों की घोषणा की, जो एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय साबित होंगे। एमएसएमई सपोर्ट और आउटरीच कार्यक्रम लॉन्च को दौरान पीएम ने 12 प्रमुख निर्णयों की घोषणा की है जिनसे एमएसएमई कारोबार तक ऋणों की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ—साथ कई सहूलियतें देने में मदद मिलेगी।



#### 12 प्रमुख निर्णयों और इसके प्रभाव ग्राफिक्स में दर्शाए गए हैं

🕒 59 मिनट में लोन	у पंजीकृत एमएसएमई को ऋण के ब्याज में राहत	500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले सभी निजी व सीपीएसई (TReDS) पोर्टल पर होंगे
एमएसएमई को तकनीकी मदद प्रदान करने हेतु 20 हब और 100 स्पोक्स	्र-© सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां ८-© अपनी 25% खरीददारी एमएसएमई से करेंगे	8 श्रम कानूनों और 10 केन्द्रीय नियमों के तहत दिया जाना वाला रिटर्न अब आपको साल में दो बार की जगह एक बार ही
फार्मा क्लस्टर के निर्माण की लागत का 70% केन्द्र सरकार वहन करेगी	सीपीएसई के लिए ळमड की सदस्यता लेना अनिवार्य	सरकारी कंपनियां एमएमएमई से अपनी खरीद का 25 प्रतिशत में से 3 प्रतिशत महिला उद्यमियों के लिए
इंस्पेक्टर राज का खात्मा और पारदर्शिता सुनिश्चित	क्षेटी गलतियों के सुधार हेतु जुर्माना घटाने के लिए अध्यादेश	पर्यावरण अनुमोदन की प्रक्रियाओं का सरलीकरण और स्वप्रमाणन को बढ़ावा

#### इस ऐतिहासिक निर्णय से सुनिश्चित होंगे

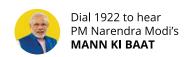


















# Sharp rise in timely wage disbursal of MGNREGA workers

The government led by PM Modi has worked tirelessly to relieve the hardship of the rural poor. One exemplary instance in this regard includes ensuring greater timely payment of wages to MGNREGA workers. Where earlier delay in wages throttled the opportunity of employment to rural people under the scheme, the intervention by the present government has alleviated the distress by providing both timely payment and increased demand for work.



Further the increase in budgetary allocation of Rs 55,000 crore during FY 2018-19, adequate utilisation of resources and its mobilisation is is symbolic of the improvement in quality of durable assets and convergence for effective livelihood diversification.

Wage payments generated within 15 days







142 crore man-days of work generated in 2018-19



**53%** of workers are women



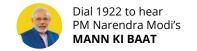
Geo-tagging of all assets created to ensure transparency



Nearly 100%
expenditure is
now through
e-FMS\*

As on 31st October 18

\*Electronic Fund Management System









### मनरेगा श्रमिकों को नियत समय पर मजदूरी वितरण के आंकड़े हुए बेहतर

प्रधानमंत्री मोदी की अगुआई वाली सरकार ने ग्रामीण गरीबों के जीवन को आसान बनाने और उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए सतत प्रयासरत है। इस दिशा में मनरेगा श्रमिकों को नियत समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। इस योजना के तहत पहले विलंब से मजदूरी मिलने की वजह से ग्रामीण रोजगार के अवसर का समुचित फायदा नहीं उठा पाते थे। मौजूदा सरकार ने समय पर भुगतान और काम की मांग में वृद्धि करके इस दिक्कत को दूर कर दिया है।



वित्त वर्ष 2018—19 के दौरान मनरेगा के बजटीय आवंटन में 55,000 करोड़ रुपये की वृद्धि, संसाधनों के पर्याप्त उपयोग के जिरए आजीविका विविधता व गरीबी कम करने में योगदान तथा स्थाई परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में सुधार देख जा रहा है।

### 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान







2018—19 में 142 करोड़ मानव दिवसों के कार्य का सृजन



श्रमिकों में <mark>53</mark>% महिलाएं



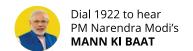
पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु सभी निर्मित संपत्तियों का भू—टैगिंग



अब ई-एफएमएस\* के माध्यम से लगभग 100% व्यय

31 अक्टूबर, 2018 तक

\*इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम









#### Farmers are the ones who take the country forward: PM Modi



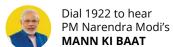


During an address via video conferencing at Krishi Kumbh in Lucknow PM Modi, reiterated the government's commitment to double the farmer's income by 2022. The Prime Minister expressed confidence that this gathering of the farmers at the event would pave way for new technology to be imbibed and better opportunities to be created in the agricultural sector.



The Prime Minister moreover stated that the present government instead of working in instalments related to the issue of agriculture is dedicated towards ushering in a holistic and comprehensive development of farmers. In this context he mentioned that the plan consist of 'Kam Lagat, Adhik Aay' which resulted in making unprecedented inclusion of scientific methods in farming.

A series of measures taken by the government in the last four years has been targeted towards lowering input costs and raising profits. Further he also asserted the practise of harnessing latest technology in farming during the interaction and called discussions on matters including judicious use of water resources and utilising technology for water storage.





# किसानों की बदौलत ही देश आगे बढ़ता है: पीएम मोदी





प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि कुंभ को संबोधित करते हुए 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि कृषि कुंभ आने वाले दिनों में कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए तकनीक और अन्य अवसरों का नया रास्ता खोलेगा।



प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कृषि और किसान से जुड़ी समस्याओं पर टुकड़ों में काम करने की पुरानी सोच के बजाय अब पूरी समग्रता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान किसानों की छोटी—छोटी मुश्किलों को दूर करने पर है। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए कम लागत, अधिक लाभ की नीति पर चलते हुए खेती में वैज्ञानिक तरीकों का अभूतपूर्व समावेश किया जा रहा है।

साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में बड़ी संख्या में सोलर पम्प देश भर के खेतों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने संवाद के दौरान जल संसाधनों के समुचित उपयोग, भंडारण की बेहतर तकनीक अपनाने और खेती—बाड़ी में नवीनतम प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर विशेष बल दिया।

